RAJYA SABHA

Tuesday, the 22nd Februrary, 1994/ 3rd Phalguna 1915 (Saka)

The House met at eleven of the Clock, The Deputy Chairman in the chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Introduction of Ministers.

INTRODUCTION OF MINISTERS

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Madam, with your permission I beg to introduce to you and through you to this august House two of my colleagues who were sworn in just a few days back - Shri Ram Lakhan Singh Yadav, Minister of Chemicals and Fertilizers and Dr. C. Silvera, Minister of State for Health and Family Welfare.

श्री शंकर दयाल सिंह: और मंत्रिमंडल में कब विस्तार होगा? (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी: इसके लिए सेपरेट नोटिस चाहिये (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Wc welcome you to the Rajya Sabha because you are coming for the first time. You would be visiting our House on your Question days and otherwise; so. welcome again.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Controlling the Prices of Cotton and Cotton Yarn

*1. SHRI N. E. BALARAM.
SHRI N. GIRI PRASAD:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a sharp rise in prices of cotton and cotton yarn, forcing the closure of 1,50,000 powerlooms and rendering about 1 million workers jobless in and around Periyar district in Tamil Nadu;

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri N.E. Balaram

(b) whether it is also a fact that this matter has been brought to the notice of Government by the powerloom mill onwers; and

(c) if so, the details thereof and what steps were taken by Government to control the rise in prices of cotton and cotton yarn?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G VENKAT SWAMY): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. A large number of powerloom units in various regions of the country have reportedly been forced to stop production due to sudden spurt in prices of cotton and cotton yarn.

(b) Yes. Sir.

(c) The Handloom, Powerloom and mill onwers have requested the Government to arrest the hike in the prices of cotton and cotton yarn immediately by improving availability of raw material. Some of the measures taken by the Government in this regard are:

(i) Decision to permit duty free import of cotton upto 5 lakh bales by spinning mills;

(ii) Stopping of unutilised export quota of cotton out of 5 lakh bales of cotton released for, export during 1993-94;

(iii) Suspension of export on 9-2-1994 in respect of the quantity of cotton already contracted for export but not yet shipped;

(iv) Reintroduction of Selective Credit Controls on cotton;

(v) Requesting the State Governments to take steps to check hoarding of cotton;

(vi) Arrangement for supply of hank yarn by spinning mills at prices which are at least Rs. 8.00 per Kg. lower than January' 94 prices.

SHRI N. E. BALARAM: Madam, Deputy Chairman, the most disturbing trend in cotton, is the price rise. Now, in this question I am raising the issue of rise in the price of yarn. In the reply given by the Minister, he has only mentioned that he has decided to take certain steps. Of course, the price is rising much higher and there is no relation between the support price and the market price at all. There is a difference of 50 to 90 per cent in the prices. I know-., the cases of handloom workers and powerloom workers in Kerala, and Tamil Nadu. A large number of workers are unemployed; maybe for some months. I don't know how long this will last. But I would like to know what effective steps the Government has taken. He has mentioned so many things. But what are the effective steps taken by the Government to curb the price rise in yarn?

SHRI G. VENKAT SWAMY: Madam, there is a decline in cotton production in Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. World cotton production has fallen due to failure of crop in Pakistan and China.

देश में काटन की जितनी जरूरत है उतना काटन जरूर हमने प्रोड्यूस किया है। मगर कुछ कोआपरेटिव फेडरेशन्स और ट्रेडर्स ने जो काटन को बड़ी तिजात में परचेज किया है जिसकी वजह से काटन प्राइसेज एकदम ऊंचे हो गये, उसके लिए सारे चीफ मिनिस्टर्स को हमने लिखा कि ये काटन प्राइसेज ऊंचे होने की वजह से फ्यूचर में हमारा जो क्लाथ का प्राइस है वह बहुत ही बढ़ा जायेगा और उसके साथ साथ एक करोड़ बीस लाख वीवर्स पर इसका काफी असर होगा। उसी तरह से एक करोड़ के करीब मिल वर्कर्स और पावरलूम वर्कर्स के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की कि यह होर्डिंग जो हो रही है। काटन की पर्टिकूलर्ली ट्रेडर्स और काअपरेटिव फेडरेशन के द्वारा उसको जब तक बाहर न लाया जायेगा रेट नहीं गिरेगा। तो हमने पहले वह कोशिश की। फिर बाद में देखा कि रेट दिन व दिन बढ़ते जा रहे हैं तो क्या किया जाये। उपसभापति महोदया, हमारा उद्देश्य यह है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कि काटन के प्राइस भी बराबर किसानों को मिलें और साथ ही साथ देश के अंदर जो प्राडक्टिविटी है काटन की टैक्सटाइल की, हैंडलूम की पावरलूम की इनमें वैलेंस रहे। हमने यह करने की कोशिश गुजिश्ता साल की और इस साल भी इसकी कोशिश करते रहे।

नतीजा यह हुआ था कि काटन के प्राइसेज बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे थे। मैं आपको साफ-साफ बताना चाहता हूं कि लास्ट इयर हमारे पास काट का 135 लाख का प्रोडक्शन था जिसमें हमने 18 लाख बेल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमिशन दिया। इस साल जब कम हो गया.....

श्री प्रमोद महाजन: 1.37 लाख में से 18 लाख एक्सपोर्ट?

श्री जी० वेंकट स्वामी: लास्ट इयर का जो टोटल प्रोडक्शन है वह मैं आपको दे रहा हूं।

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Out of the total production of 1.37 lakh tonnes,you exported 18 lakh tonnes

उपसभापति: बोलने तो दीजिए।

श्री जी० वेंकट स्वामी: यह जो फिगर्स मैं दे रहा हूं यह लास्ट इयर का है **(व्यवधान)** लाख में है।

उपसभापति: मंत्री जी बोलिए।

SHRI N E. BALARAM: Let him give the answer.

उपसभापति: आपने यह जो सवाल पूछा था उसका जवाब दे दीजिए।

श्री जी० वेंकट स्वामी: उसी का जवाब दे रहा हूं। काटन के सिलसिले में जो भी क्वेश्चन अभी किया है...**(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी: तफसील से समझा रहे हैं समझ लें।

श्री जी० वेंकट स्वामी: तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स अंदर जो पावरलूम बंद हो गये हैं - जो आनरेबुल मेम्बर ने क्वेश्चन पूछा था पावरलूम और हैंडलूम की हालत बहुत खराब है उसका वजह से काटन की क्या पालिसी

है, गवर्नमेंट ने क्या पालिसी अख्तियार की है तो मैं उसका खुलासा करने जा रहा था। लास्ट इयर प्रोडक्शन अच्छा था तो हमने ज्यादातर एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए परमिशन दिया ताकि किसानों को अच्छा रेट मिले और इस साल भी हमने पांच लाख बेल्स उस वक्त दिया कि डीलर्स के हाथ में न जाये किसानों के हाथ में जाये। सेप्टेम्बर में हमने पांच लाख बेल्स के एक्सपोर्ट का परमिशन दिया। मगर उस पांच लाख बेल्स में ट्रेडर्स को न देते हुए कोआपरेटिव आर्गेनाइजेशन को हमने दिया जिसमें कुछ एक्सपोर्ट हुआ और कुछ एक्सपोर्ट बाकी थ तो हमने देखा कि रेट बढ़ते जा रहे हैं। किसानों को जिस तरह से भी हो रेट मिलना चाहिए। पिछले साल से इस साल किसानों को चंद जगह डबल मिल रहा है और बंट जगह 43 परसेंट से 102 परसेंट तक रेट में इजाफा लास्ट इयर से अब तक मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है - हमारे आनरेबुल मेम्बर को मैं यह बताना चाहता हूं.....(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह: एक मिनट के सवाल का एक मिनट का जवाब होना चाहिए....(व्यवधान)

श्री जी० वेंकटस्वामी: मैंने पूरा उत्तर दे दिया है. अगर सप्लीमेंटरी पूछेंगे तो मैं इन्फर्मेशन देने के लिए तैयार हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not one minute.

SHRI DIG VIJAY SINGH: He has already taken ten minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: just a minute. The (c) part of the question itself is very big. It says:

> "If so, the details thereof and what steps were taken bv Government to control the rise in prices of cotton and cotton yarn?"

Now, if you want that the Minister should give a short answer, the question should also be short.

SHRI N. E. BALARAM: Let him be allowed to speak We want to have the information.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You put another supplementary.

SHRI V. NARAYAN SAMY: let him elaborate it *(Interruptions)* .....

श्री जी० वेंकटस्वामी: उपसभापति जी, देश के अंदर जो कॉटन के हालात और रेट हैं वह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और आनरेबल मैम्बर्स और अगर सुनने की कोशिश करें तो मैं पूरी तरह से पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You put the second supplementary.

SHRI N E. BALARAM: Madam, in regard to the statistics about the availability of cotton, ! don't know whether we have got a very clear picture of it because the Minister himself was saying some time ago that the domestic need, domestic reqirement would come to 12.5 million bales of cotton and the availability would come to 17.5 million bales of cotton. Then there is no question of scarcity of cotton at all. The real problem is the problem of hoarding by the 'raders whom we call sometimes as the professional speculators. They are hoarding the stocks. That is the main problem for the increase in the price this time. The Minister, in his answer, has stated that the State Government are requested to take steps to check hoarding, etc. 1 hope the Ministry is monitoring the entire thing. What is the latest position? Has the Minister taken any steps to arrest the hoarding so that the handloom workers, the powerloom workers are supplied yarn at reasonable prices?

Secondly, in regard to the re-introduction of selective credit controls. I. would like to know whether any instructions have been issued by the Reserve Bank. I would also like to know what concrete steps have been taken. These are the wishes, the desires of the Government. I would like to know what concrete steps have been taken by the Government and the result of those steps.

श्री जी० वेंकटस्वामी: उपसभापति जी, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1988-89 में हमारा जो कॉटन का प्रोडक्शन था 106.00, 1989.90 में 135.00, 199.-92 में 119.00, 1992-93 में 135.00 और 1993-94 में इस साल 125.00 लाख बैल्ज। दिस इज द प्रोडक्शन पोजीशन। उपसभापति जी, सवाल आनरेबल

मैंबर ने किया है कि आपने क्या-क्या स्टैप्स लिए। जैसे ही यह यार्न प्राइस इन्क्रीज होता जा रहा था एक तरफ तो हैंक यार्न और हैंडलूम वीवर्ज़ के लिए और दूसरा कोन यार्न के लिए जो हमारे फिगर्ज़ हैं जब अगस्त के महीने में 63.72 यार्न प्राइस था और जिसका पर के०जी० 73.11 इकरीज हुआ जो लास्ट ईयर में है हैंक यार्न 63 था एंड कोन यार्न प्राइस लास्ट ईयर 70.88 था नाउ 80.10 रु० 6 रूपीज़ इन्क्रीज इन कोन यार्न दैट इज़ यूजिंग फार पावरलूम।

मैंने मिल ओनर्स की मीटिंग की और उनसे कहा कि आप यार्न फारेन एक्सपोर्ट करना है तो आप हैंक यार्न प्राइस जोकि लास्ट थ्री इयर्स पहले हैंडलूम वीवर्स के लिए बढ़ गए हैं, उनके लिए आप क्या कंसेशन देंगे और पिछले साल के अक्टूबर में जो रेट होंगे उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कंपेनसेशन देंगे या सहूलियत देंगे। उपसभापति जी, मैं आपको इनफार्म कर रहा हूं कि जो स्पिनिंग मिल ओनर्स है उन्होंने पर के०जी० 8 रुपए....**(व्यवधान)**....

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam, can you sum up what he is saying? It is beyond our comprehension.

श्री एस० एस० अहलुवालिया: ये काटन के व्यापारी है जो विरोध कर रहे हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, they wanted to know, and he has explained the situation. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question itself is very vague. So, the answer has to be big. He is giving an answer. Let him give an answer.

श्री जी० वेंकटस्वामी: उपसभापति जी, यह क्युश्चन बहुत इम्पोर्टेन्ट है। आनरेबल मेंबर सुनें तो बहुत ही अच्छा है। देश में काटन की हालत बहुत खराब है और इस बारे में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप मेहरबानी कर के सुनने की कोशिश करें। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि तीन साल पहले हैंटलूम वीवर्स की जिस तरह से स्टार्विंग डेथ्स हुई, ऐसी नौबत फिर आई है जिसके लिए गवर्नमेंट ने सख्ती से एक्शन लिया है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है और रिजर्व बैंक गवर्नर को लिखा कि बैंक्स होर्डिंग करने के लिए जो पैसा दे रहे है, उसको आप रोकिए। उन्होंने उसको भी रोक दिया है। एक्सपोर्ट को भी हमने बंद किया है और इसको पूरी तरह से घटाने की कोशिश की है। बैंक यार्न को 8 रुपया कम किया है और अक्टूबर में जो रेट्स थे उनको मेंटेन करने की गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही .....**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह: और ताली ठोको .....**(व्यवधान)**...यह क्युश्चन-आंसर का तरीका है?

श्री जी० वेंकटस्वामी: उपसभापति जी, हैंडलूम वीवर्स के लिए 8 रुपया कम हुआ है। अक्टूबर के रेट्स अगर मेंटेन किये तो हैंडलूम वीवर्स को हैंक यार्न सप्लाय करने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे। उसी तरह से पावरलूम के बारे में आनरेबल मेंबर ने क्युश्चन किया है? उसके बारे में 6 रुपए का इजाफा हुआ है.... **(व्यवधान)** .....

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry, this is not proper. Let there be order in the House. When the Minister is answering, the Member who has asked has a right to hear. So, please do not disturb. If you do not want to hear, you may not hear. But you allow the Member who has put the question to hear. And I want to know what the Minister is saying.

श्री जी० वेंकटस्वामी: उपसभापति जी, टैक्सटाइल मिनिस्ट्री को जो एक्शन लेना है, वह हम ले रहे हैं और रेट्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उपसभापति जी दो चीजें इम्पोर्टेन्ट है, एक तो किसान को भी बराबर सप्लाय मिले और दूसरे गरीब वीवर्स और पावरलूम वर्कर्स को भी काम पूरी तरह से मिले और ऐसी कोई कमी नहीं हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: किसान की बात कहां से आ गयी?... .**(व्यवधान)**...किसान को कहां देने की बात कर रहे हैं आप?

श्री जी० वेंकटस्वामी: किसान को लास्ट इयर से 500 रुपया ज्यादा दे रहे हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. Mr. Mann, will you please keep quiet? Now, Mr. Giri Prasad to put his supplementary.

SHRI N. GIRI PRASAD: Madam, the hon. Minister is in difficulty to answer this question becasue there are many interests that arc involved, the peasants

who produce the cotton, the powerloom weavers, the handloom weavers, the consumers and the export needs. There are many things involved in this. But in view of the inflationary pressure on the economy, the price that the farmer is getting is very low--at least not this year.

The minimumprice fixed by the Government is the floor price; it is only a minimum price. There is no restriction that the peasant has to sell only at the minimum price of floor price. In view of the inflationary pressure, the Government must keep the interests of the farmers also in mind. At least, the market forces this year are helping the peasants to some extent. The Government should have a policy which safeguards the interests of various sections of the people. I would like to know from the hon. Minister whether he can fix the cotton price at the minimum level that is more than what is fixed now, say, at about Rs. 1500/- so that the farmer also gets a proper price and the Government gets sufficient quantity of cotton yarn to help the handloom and power-loom workers.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He wants to know whether you can fix a price at more than what has already been fixed

आज की जो मिनियम प्राइस है, उससे ऊपर 1500/- रुपए तक आप कर सकते हैं?

श्री जी० वेंकटस्वामी: मैडम, लास्ट ईयर से जो मिनियम प्राइस, सपोर्ट प्राइस जो पिक्स हुआ था, इस साल जो है 100/- रुपए ज्यादा किया है सपोर्ट प्राइस को। मगर, उपसभापति जी, इस वक्त जो है प्राइस से, जैसा कि लास्ट ईयर जो प्राइस था उससे, 500 रुपए से 700/- रुपए तक इन्क्रीज हुआ है। यह मैं ऑनरेबिल मैम्बर को समझना चाहता हूं कि किसान को इस साल जो है बहुत ज्यादा मिल रहा है और इस साल यह हमने सपोर्ट प्राइस में भी 100/- रुपए का इजाफा किया। अगर किसान यह कहता है कि हमको बराबर प्राइस नहीं मिल रहा है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पंजाब जाइए, गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, आंध्रा जाइए, लास्ट ईयर से अब जो प्राइस, ऑनरेबिल मैम्बर विलोग्स टू आंध्र प्रदेश, उनको मालूम है यह, उपसभापति जी, कि जो प्राइस मिल रहा था उससे 550/- रुपए ज्यादा प्राइस किसान को मिल रहा है।

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: I can understand the predicament and the dilemma in which the Government finds itself today on this issue. On the one hand, they have to take care of the farmer and see that the cotton grower gets remunerative price and at the same time, they have to take care of the consumer and keep the price at the minimum. The hon. Minister was talking about the steps he has taken against the hoarders. But this will give only short-term results. We have to think of long-term arrangement. Any hasty step to import cotton will be questioned by the hon. Finance Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you please ask your question because we have already spent about 23 minutes on this question?

SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: My question is whether the Government will come forward to organise handloom weavers's societies and also similar societies for the powerloom weavers and form a federation which will purchase cotton and also gin the cotton and also, if necessary, will have mills on lease for spinning. In order to help the powerloom weavers, why don't they think of creating buffer stocks?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Arc you going to form some federation?

SHRI G. VENKAT SWAMY: We will discuss it and I will inform the hon. Member.

उपसभापति: मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी। पहला सवाल है आपका? पहली दफा आप सवाल पूछ रहे है हाऊस में? जल्दी पूछ लीजिए।

मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी: मैडम, मैं आपके जरिए यह कहना चाहता हूं कि आमतौर से कभी रूई का दाम बढ़ता है, कभी सूत का दाम बढ़ता है या घटता है तो हर हाल में बुनकर को नुकसान पहुंचता है। क्या मंत्री जी ऐसा नहीं कर सकते कि जिस तरह से गन्ने का प्राइस जो है तय करते है, चीनी का

मुकर्रर करते है वैसे ही कपास का भी भाव मुकर्रर करें और सूत का भाव मुकर्रर करें? क्योंकि सूत की कीमत बढ़ती है तब भी बुनकर को नुकसान होता है और घटती है तब भी नुकसान होता है और इस पर कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। हर दो साल, तीन साल, एक साल के बाद इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है कि कभी कपास ज्यादा पैदा हो जाती है और इससे किसान का नुकसान हो जाता है और कभी कम हो जाती है तो फिर बुनकर का नुकसान हो जाता है। इस वक्त बिहार या उत्तर प्रदेश के बुनकर ज्यादा परेशान हैं, करघा बंद है, पावरलूम बंद है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी पालिसी बनाई जाए।

उपसभापतिः बैठिए, जवाब देने दीजिए। आप चिट्ठी लिखकर मंत्री जी को अपने सजेशन्स तो भेज दीजिए।

श्री जी॰ वेंकटस्वामीः उप सभापति जी, नोमानी साहब हमारे बुनकरों के नुमाइंदे है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो देश के अंदर बुनकरों की हालत खराब होती जा रही है दिन-प्रतिदिन, उसी के लिए मिल-ओनर्स को बुलाकर हमने जो रेट जनवरी में था, उसी रेट पर बुनकरों को यार्न सप्लाई करने का निर्णय किया है और इससे बुनकरों की परेशानी दूर हो सकती है। इसलिए हमने निर्णय किया है और वह अमल में आ रहा है। अमल में आते ही आपको पता चलेगा कि बुनकरों की हालत जो पिछले साल थी, उसी लेवल में लाने की हम कोशिश कर रहे है।

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM THAILAND

THE DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make.

We have with us, seated in the Special Box, members of a parliamentary delegation from Thailand, currently on a visit to our country under the distinguished leadership of His Excellency Prof. Marut Bunnag, Speaker of the House of Representatives and President of the National Assembly of Thailand.

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the leader and other members of the delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here they would be able to see and learn more about our parliamentary system, our country and our people, and their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Thailand.

Through them, we convey our greetings and best wishes His Majesty the King, the Government, the Parliament and the friendly people of Thailand.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS CONTD. Q. NO. 1 CONTD.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 2. *(Interruptions)* In regard to Question No. 1, you can request the Chairman for a special discussion on the whole subject and I am sure the Minister would be ready to discuss.

श्री भूपेन्द्र सिंह मानः मैडम, इसके बारे में हाफ-एन-ऑवर डिस्कशन होना चाहिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I said it. You write to the Chairman.

श्री भूपेन्द्र सिंह मानः मैडम, इसमें जो कहा है मिनिस्टर साहब ने, वह मिनियम सपोर्ट प्राइस तो एक बात है और यह मैक्सिमम पर लगाना चाहते हैं, इसके बारे में तो कोई बात आई नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीयः आधा घंटा तो ऐसे ही हो गया है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mann, this is not the way. I said that you write to the Chairman. It has got wide ramifications because on the same question there is divergence of opinion. Therefore, it is better that you ask for a special discussion and I am sure the Chairman will consider it. You please write to the Chairman.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: We should have a half-an-hour discussion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Half-an-hour discussion or one hour discussion or whatever it is. *(Interruptions)*

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Madam, please allow me.

THE DEPUTY. CHAIRMAN: You write to the Chairman, Now, Question No. 2.

Bogus Claims of Insurance

*2. SHRI MOHAMMED AFZAL *ALLIAS* MEEM AFZAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that submission of bogus claims of insurance worth Rs. 1802 crores were allowed by Life Insurance Corporation of India in the year 1992-93;

(b) if so, what action has been taken by Government in this regard;

(c) what are the names of persons who were found involved in this act; and

(d) what steps have been taken by Government to prevent recurrence of such incidents in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) The Life Insurance Corporation of India have reported that they did not settle any bogus claim in the year 1992-93.

(b) to (d). Do not arise.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: मैडम, मंत्री जी ने बताया कि एल० आई० सी० ने 1802 करोड़ रुपए के बोगस क्लेम नहीं दिए है। ...(व्यवधान)...

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

†[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: मैडम, मंत्री जी ने बताया कि एल० आई० सी० ने 1802 करोड़ रुपए के बोगस क्लेम नहीं दिए हैं]

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Madam, please allow me.I have been requesting you. You arc not permitting me to put my question

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kotaiah, will you please sit down?

अफजल साहब, आप सवाल पूछिए।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: मैडम, मै मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एल० आई० सी० ने अगर बोगस क्लेम नहीं दिए हैं तो क्या 1992-93 में एल० आई० सी० ने 1802 करोड़ रुपए का बोगस इन्श्योरेंस किया है? क्या उन्हें इसकी कोई जानकारी है? क्या उन्हें इसकी भी कोई जानकारी है कि 1991-92 के अंदर भी इस तरह के करोड़ों रुपए के बोगस इन्श्योरेंस किए गए हैं?

†[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: मैडम, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एल० आई० सी० ने अगर बोगस क्लेम नहीं दिए हैं तो क्या 1992-93 में एल० आई० सी० ने 1802 करोड़ रुपए का बोगस इन्श्योरेंस किया है? क्या उन्हें इसकी कोई जानकारी है? क्या उन्हें इसकी भी कोई जानकारी है कि 1991-92 के अंदर भी इस तरह के करोड़ों रुपए के बोगस इन्श्योरेंस किए गए हैं]

डा० अबरार अहमद: मैडम, जहां तक मूल प्रश्न के अंदर माननीय सदस्य ने जीव बीमा निगम के द्वारा बीमे के 1802 करोड़ रुपए के मूल्य के फर्जी दावों के भुगतान की बात कही है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जीवन बीमा निगम में जो दावों का भुगतान किया जाता है, उसके मात्र दो ही तरीके हैं।

या तो पालिसी मैच्योर हो जाए, तब किया जाता है, या कोई कैजुयल्टी हो जाए, तब किया जाता है। तो फर्जी दावे का भुगतान होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।